

<><><><><><><>

- मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कल पत्तन प्रबंधन बोर्ड और जिला प्रशासन सहित प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक की।
- पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार दो हजार टेइस की कल नई दिल्ली में घोषणा की गई।
- गरीबी रेखा से ऊपर, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले समूह के बचे हुए राशन कार्ड लाभार्थियों से इकतीस अक्टूबर तक ई-के वाई सी कराने का अनुरोध किया गया है।
- समाज कल्याण निदेशालय ने 'शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव' पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
- शैक्षणिक सत्र दो हजार चौबीस-पच्चीस के लिए अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों के लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

<><><><><><><>

मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कल पत्तन प्रबंधन बोर्ड और जिला प्रशासन सहित प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक की। बैठक में लंबे समय से लंबित मुद्दों जैसे नाव सर्वेक्षण, नाव पंजीकरण और पुनर्मूल्यांकन तथा द्वीपसमूह में समुद्री और पर्यटन क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए अनुमोदन में तेजी लाने और प्रक्रियाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में नाव से संबंधित मामलों में समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए इकतीस अक्टूबर, तक की समय सीमा निर्धारित की गई, जिससे नाव मालिकों और संचालकों को काफी राहत मिलेगी। बैठक में समुद्री कर्मियों के लिए योग्यता प्रमाणपत्र और जीपी रेटिंग का नवीनीकरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने पी एम बी को नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज करने का निर्देश दिया, ताकि पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने इन मुद्दों के प्रभावी और समय पर समाधान को सुनिश्चित करने के लिए पी एम बी, जिला प्रशासन और अन्य हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

<><><><><><><>

पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार दो हजार टेइस की कल नई दिल्ली में घोषणा की गई। राज्यों की श्रेणी में ओडिशा ने पहला और उत्तर प्रदेश को दूसरा पुरस्कार मिला है। गुजरात और पुदुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बाइस अक्टूबर को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। नौ श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित कुल अड़तीस विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नई दिल्ली में कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने जल प्रबंधन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विजेताओं की प्रशंसा की।

<><><><><><><>

गरीबी रेखा से ऊपर अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले समूह के बचे हुए राशन कार्ड लाभार्थियों से इकतीस अक्टूबर तक ई-के वाई सी कराने का एक बार फिर अनुरोध किया गया है। निर्धारित तिथि के बाद नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी लाभार्थी नागरिक आपूर्ति विभाग के कमरा नम्बर बीस या अपने-अपने आपूर्ति विभाग के इकाईयों से संपर्क कर ई-के वाई सी करा सकते हैं। ऐसे सभी बचे हुए लाभार्थियों की सूची संबंधित उचित मूल्य की दुकानों में भी जानकारी के लिए उपलब्ध कराया गया है।

इस बीच, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले समूह के एक से सत्रह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का पांच वर्ष की आयु होने से पहले ही आधार बनाया गया था। इस कारण इनका ई-के वाई सी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। ऐसे सभी लाभार्थियों से भी अपने नजदीकी केन्द्रों में जाकर आधार को तर्कसंगत बनाने को कहा गया है। आपूर्ति विभाग की ओर से लगातार आधार शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसे लाभार्थी एक से सत्रह वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों के आधार में सुधार के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><>

समाज कल्याण निदेशालय ने 'शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव' पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को मादक पदार्थों की मांग को कम

करने के महत्व और समुदाय के भीतर मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना था। कार्यक्रम में एन ए पी डी डी आर के परियोजना सहायक अंचम्मा के नेतृत्व में एक व्यापक सत्र का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने नशीली दवाओं की मांग को कम करने में समुदाय की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कर्मचारियों को जागरूकता फैलाने और मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित व्यक्तियों का समर्थन करने में सक्रिय होने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

समाज कल्याण निदेशक डॉ. नितिन शाक्या ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बढ़ती समस्या और इसके व्यापक सामाजिक परिणामों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "नशीली दवाओं का दुरुपयोग केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है; यह परिवारों, समुदायों और पूरे समाज को प्रभावित करता है।" उन्होंने कहा, "जब कोई व्यक्ति नशे की लत का शिकार हो जाता है, तो यह केवल उसका जीवन ही नहीं होता है जो दांव पर लगा होता है। इसका असर उसके परिवार, उसके समुदाय और पूरे समाज पर पड़ता है।"

<><><><><><><>

शैक्षणिक सत्र दो हजार चौबीस—पच्चीस के लिए अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों के लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए उम्मीदवार जिनके अभिभावकों की वार्षिक आमदनी किसी स्त्रोत से सलाना ढाई लाख से अधिक नहीं है, वे इककतीस दिसम्बर तक आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए भी उम्मीदवार अगले वर्ष इककतीस जनवरी तक और अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजना के लिए इककतीस दिसम्बर तक ही उम्मीदवार आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन जमा करने होंगे। इसके लिए सभी स्कूल और कॉलेजों में सहायता के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। सभी पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से यूटी प्रशासन और भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहयोग का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया है।

<><><><><><><>

उद्योग विभाग और द्वीप प्रशासन ने नई दिल्ली के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सहयोग से कल मिडिल प्लाइंट स्थित उद्योग विभाग के सम्मेलन कक्ष में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान दो हजार चौबीस और आर सी बी पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर नई दिल्ली के डी पी आई आई टी और इनवेस्ट इंडिया के उप सचिव डॉ. भुवनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि थे। कार्यशाला में उद्योग विभाग के सचिव डॉ. सत्येंद्र सिंह दुरसावत और उद्योग विभाग के निदेशक अभिषेक भुकल के साथ—साथ डीपीआईआईटी, नई दिल्ली के अवर सचिव श्री सुशील कुमार ने भाग लिया। कार्यशाला में विभिन्न हितधारकों, औद्योगिक संघों और व्यापारिक संघों के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश को व्यापार सुधार कार्य योजना दो हजार बाईस रॅकिंग में दो नागरिक केंद्रित सुधार क्षेत्रों में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन के विभिन्न विभागों से नियामक संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह से संबोधित तीस ऑनलाइन सेवाओं और अड्सर नो योर अप्रूवल्स को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल पर लॉन्च किया गया था।

<><><><><><><>

होसुर, तमिलनाडु में दो नवम्बर से आयोजित होने वाले उनचासवें राष्ट्रीय सब—जूनियर शतरंज चैम्पियनशिप के चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की ओर से बीस अक्तूबर को डेरीफार्म के सामुदायिक हॉल में पन्द्रह वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए सब—जूनियर चेस चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इनमें से सर्वश्रेष्ठ चार खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। पहली जनवरी दो हजार नौ या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी इस चैम्पियनशिप में भाग ले सकते हैं। इन खिलाड़ियों का वर्ष दो हजार चौबीस—पच्चीस ए आई सी एफ में पंजीकरण होना अनिवार्य है। इच्छुक खिलाड़ी अट्ठारह अक्तूबर तक चेस एसोसिएशन के पास सुबह दस बजे से शाम पांच बजे के बीच अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं।

<><><><><><>